शहर में हजारों भवन अवैध; डेढ़ सौ असुरक्षित घोषित, खतरे में जिंदगियां

दिल्ली में इमारत ढहने की घटना के बाद से बढ़ी चिंता, कई मकानों को है खतरा

अमर उजाला ब्यूरो

शिमला। दिल्ली में पांच मंजिला इमारत ढहने की घटना के बाद राजधानी शिमला में भी खतरे की जद में आए भवनों और असुरक्षित मकानों के आसपास रह रहे लोग चिंता में हैं। बरसात के चलते इनकी परेशानी बढ़ गई है।

शहर में हजारों बहुमंजिला भवन ऐसे हैं जो बिना नक्शे के बने हैं। इनमें से 150 से ज्यादा भवन नगर निगम असुरक्षित घोषित कर चुका है। रिहायशी इलाकों के बीच खड़े इन असुरक्षित और जर्जर भवनों ने शहरवासियों की चिंता बढ़ा दी है।

निगम के अनुसार असुरक्षित घोषित किए यह भवन रहने योग्य नहीं हैं और इन्हें तुरंत खाली करने के निर्देश दिए हैं। इन भवनों को गिराने के आदेश भी जारी किए जा चुके हैं, लेकिन नगर निगम के इन आदेशों पर लोगों, खासकर किरायेदारों ने ऊपरी अदालतों से स्टे ले रखा है।

ऐसे में इन्हें अभी तक गिराया नहीं जा सका है। इन भवनों में अभी भी लोग रह रहे हैं। इन मकानों से अब आसपास के घरों में रहने वाले लोग भी डर के साये में जी रहे हैं। शहर में गलत तरीके से की गई खोदाई से भी इस साल कई मकान खतरे की जद में आ चुके हैं। शहर के मैहली, संजौली, कुफ्टाधार, पंथाघाटी में दर्जनों मकान गलत खोदाई के कारण दरकने की कगार पर हैं। दिल्ली की घटना के बाद अब यह लोग चिंता में हैं।

बरसात और हिमपात के दौरान जर्जर भवनों के गिरने का रहता है खतरा

इन इलाकों में सबसे ज्यादा जर्जर भवन

शहर के लोअर बाजार, रामबाजार, सब्जी मंडी, छोटा शिमला, कसुम्पटी, बालूगंज, संजौली और लक्कड़ बाजार में सबसे ज्यादा पुराने, जर्जर और असुरक्षित भवन हैं। इनमें कई भवन पांच से छह मंजिला तक हैं। मकान मालिकों और किरायेदारों के विवाद के चलते इन्हें खाली नहीं करवाया जा सका है।

नियमानुसार करते हैं कार्रवाई

नगर निगम वास्तुकार राजेश शर्मा ने कहा कि असुरक्षित घोषित किए मकानों को लेकर नियमानुसार कार्रवाई की जाती है। असुरक्षित घोषित होने पर मकान खाली करवाया जाता है और इसे गिराया जाता है। कई बार लोग स्टे ले लेते हैं जिसमें फिर ऊपरी अदालत के आदेश का इंतजार किया जाता है। शहर में बेसमेंट को भी खोलने के लिए अनुमति लेना अनिवार्य है।

शिमला के छात्र आवासों पर सवाल; निजी कमरों, पीजी में रहने को मजबूर हैं छात्र

शिमला। दिल्ली में छात्रावास की इमारत ढहने की घटना ने शिमला में भी चिंता बढ़ा दी है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (एचपीयू) और सैकड़ों कोचिंग केंद्रों में हजारों विद्यार्थी पढ़ते हैं। छात्रावासों में सीमित सीटों के कारण बड़ी संख्या में विद्यार्थी बाहर रहते हैं। यह विद्यार्थी किराये के कमरों, निजी छात्रावासों और पीजी में रहने को मजबूर हैं।

शिमला में एचपीयू के अलावा कोटशेरा, आरकेएमवी और संजौली बड़े शिक्षण संस्थान हैं। इसके अलावा शहर में बहुत से कोचिंग संस्थानों में पढ़ाई करने के लिए छात्र शिमला आते हैं। समरहिल, लॉन्गवुड और संजौली में बड़ी संख्या में छात्र रहते हैं। कई भवनों में छोटे कमरों में अधिक विद्यार्थियों को रखा जाता है।

इससे हवा, रोशनी और आवाजाही की पर्याप्त व्यवस्था नहीं रहती। सबसे गंभीर सवाल भवन सुरक्षा को लेकर है। कई निजी पीजी और छात्रावास पुराने भवनों में चलते हैं। इनमें आपातकालीन निकास, अग्निशमन उपकरण और सुरक्षित विद्युत व्यवस्था की स्थिति की जांच जरूरी है। संकरी सीढ़ियां और सीमित निकासी मार्ग आपात स्थिति में बड़ा खतरा बन सकते हैं।

समरहिल, लॉन्गवुड और संजौली में बड़ी संख्या में छात्र रह रहे छोटे कमरों में

भवन की क्षमता से अधिक विद्यार्थियों को रखने की शिकायतें भी सामने आती रही हैं। एचपीयू की एसएफआई इकाई के अध्यक्ष मुकेश ने कहा कि ऐसे आवासों में विद्यार्थियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी तय होना जरूरी है। एबीवीपी के परिसर सचिव अक्षय ने कहा कि शिमला में भी छात्रावासों का व्यापक सुरक्षा सर्वे जरूरी है। विद्यार्थियों की संख्या के अनुपात में सुरक्षित छात्रावास बढ़ाने की जरूरत भी है। संवाद

पैसा न मिलने से शहर में काम ठप, आज केंद्र से ग्रांट का मामला उठाएंगे महापौर

केंद्र से एमसी को मिलता है 30 करोड़ रुपये से ज्यादा का बजट

अमर उजाला ब्यूरो

शिमला। राजधानी में आर्थिक तंगहाली से जूझ रहा नगर निगम अब केंद्र सरकार से अनुदान जारी करने का मामला उठाने जा रहा है। इसके लिए महापौर सुरेंद्र चौहान केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के अधिकारियों से मंगलवार को मुलाकात करेंगे।

महापौर केंद्र से इस वित्तीय वर्ष का पैसा जल्द जारी करने की मांग करेंगे। शहरी निकायों को इस साल अब तक यह अनुदान जारी नहीं हुआ है। इसके लिए महापौर सुरेंद्र चौहान अतिरिक्त आयुक्त डॉ. भुवन शर्मा के साथ सोमवार शाम दिल्ली रवाना हो गए हैं।

दिल्ली में चैलेंज फंड के इस्तेमाल को लेकर एक कार्यशाला आयोजित की जा रही है। आठ सितंबर से शुरू होने वाली यह कार्यशाला दो दिन चलेगी।

इसमें चैलेंज फंड के तहत करवाए जाने वाले कार्यों समेत अन्य केंद्रीय योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी। शिमला शहर में भी चैलेंज फंड के तहत कई बड़े प्रोजेक्ट तैयार किए हैं। इनमें सब्जी मंडी में बनने वाला नगर निगम का नया परिसर भी शामिल है।

कार्यशाला के दौरान महापौर केंद्रीय मंत्रालय के अधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे। इस दौरान केंद्र से नगर निकायों को जारी होने वाली ग्रांट जल्द जारी करने की मांग उठाई जाएगी। इसके अलावा आरडीजी से ग्रांट पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर भी जानकारी ली जाएगी।

इस साल नहीं मिला एक भी पैसा

शिमला नगर निगम को इस वित्तीय वर्ष में केंद्र से अब तक एक भी पैसा नहीं मिला है। हर साल केंद्र से निगम को 30 करोड़ रुपये से ज्यादा का अनुदान मिलता है। यह राशि दो से तीन किस्तों में जारी होती है। कमाई के साधन घटने से नगर निगम की आर्थिक हालत खराब है और शहर में नए काम ठप हो चुके हैं। ऐसे में अब महापौर केंद्र के समक्ष अनुदान जारी करने का मामला उठाएंगे। महापौर ने कहा कि उन्होंने कई विभागों के अधिकारियों से बैठक के लिए समय लिया है। प्रयास रहेगा कि जल्द शिमला को केंद्र से आर्थिक मदद मिल सके।

केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के अधिकारियों से करेंगे पैसा जारी करने की मांग

घुंडा भड़ेच में चलाया स्वच्छता अभियान

कोटखाई (रोहड़ू)। घुंडा भड़ेच पंचायत में महिला ग्राम सभा का आयोजन किया गया। प्रधान तनुजा शर्मा की अध्यक्षता में हुई इस सभा में महिलाओं से जुड़े विकास, सामाजिक और जागरूकता विषयों पर चर्चा हुई। सभा में भांग उखाड़ो अभियान, नुक्कड़ नाटक और जागरूकता रैली पर बात हुई।

स्वयं सहायता समूहों के विकास पर भी चर्चा की गई। महिला सशक्तीकरण सहित कई गतिविधियों पर विचार किया गया। इस दौरान महिलाओं ने पंचायत भवन के आसपास प्लास्टिक कचरा संग्रहण अभियान चलाया। उन्होंने स्वच्छता का संदेश दिया और लोगों को प्लास्टिक के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया। साथ ही, महिलाओं ने ग्राम पंचायत भवन के समीप पौधरोपण अभियान भी आयोजित किया। इस अवसर पर विभिन्न पौधे लगाए गए। पर्यावरण संरक्षण और हरित पंचायत के निर्माण का संदेश भी दिया गया। संवाद

निष्काम सृजन फाउंडेशन के कार्यक्रम में मौजूद महिलाएं। संवाद

मासिक धर्म में असामान्य बदलाव और गांठ को न करें नजरअंदाज

शिमला। महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ी छोटी-छोटी समस्याएं कई बार गंभीर बीमारी का संकेत हो सकती हैं। मासिक धर्म में असामान्य बदलाव, लगातार पेट या पेल्विक हिस्से में दर्द, पेशाब में जलन, स्तन में गांठ या मेनोपॉज के बाद रक्तस्राव जैसे लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।

यह बात निष्काम सृजन फाउंडेशन की ओर से सोमवार को मालरोड स्थित गार्टन कासल के अकाउंटेंट जनरल ऑफिस में आयोजित जागरूकता कार्यशाला में डॉ. श्रेया वासुदेवा ने कही। उन्होंने बताया कि समय रहते जांच और उपचार से कई गंभीर बीमारियों से बचाव संभव है। कार्यशाला में महिला कर्मचारियों ने स्वास्थ्य से जुड़े अनेक सवाल खुलकर पूछे।

डॉ. श्रेया वासुदेवा ने उनके प्रश्नों का सरल और व्यावहारिक तरीके से जवाब दिया। प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल पुरुषोत्तम तिवारी के सौजन्य से आयोजित कार्यशाला में 50 कर्मचारियों ने भाग लिया। संवाद

प्रॉसिक्यूटर्स वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष बने प्रशांत सिंह

बिलासपुर। हिमाचल प्रदेश अटॉर्नी (प्रॉसिक्यूटर्स) वेलफेयर एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी का गठन कर दिया गया है। बिलासपुर में आयोजित बैठक में एचपीपीडब्ल्यूडी, शिमला में तैनात डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी प्रशांत सिंह को एसोसिएशन का प्रदेश अध्यक्ष सर्वसम्मति से चुना गया। बैठक में प्रदेशभर से एसोसिएशन के सदस्यों ने हिस्सा लिया। इस दौरान अभियोजन अधिकारियों के कल्याण, पेशेवर हितों और सेवा संबंधी मामलों पर चर्चा की गई।

बैठक एसोसिएशन के अध्यक्ष कपिल देव शर्मा और वरिष्ठ उपाध्यक्ष कुलभूषण गौतम की मौजूदगी में हुई। बैठक में सदस्यों ने निवर्तमान पदाधिकारियों की ओर से एसोसिएशन की मांगों और समस्याओं को सरकार तथा सक्षम अधिकारियों के समक्ष उठाने के लिए किए गए प्रयासों की सराहना की। इसके बाद संगठन के उद्देश्यों और कल्याणकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए नई कार्यकारिणी के गठन का निर्णय लिया गया।

बिलासपुर में हुई बैठक में सर्वसम्मति से हुआ चुनाव नई कार्यकारिणी गठित

चुनाव प्रक्रिया में प्रशांत सिंह के नाम पर सभी सदस्यों ने सहमति जताई और उन्हें प्रदेश अध्यक्ष चुना गया। इसके बाद उन्होंने नई कार्यकारिणी का गठन किया। कांगड़ा के जिला अटॉर्नी एनएस चौहान, एचपीपीडब्ल्यूडी मुख्यालय के जिला अटॉर्नी जगदीश कुमार रजटा, हमीरपुर में एचपी राज चयन आयोग के डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी राहुल चोपड़ा और रेरा के डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी गीतरंजन भारद्वाज को सलाहकार बनाया है। एचपी सचिवालय में जिला अटॉर्नी (होम) नवीन चंदर और मंडी में जिला अटॉर्नी (एसवीएसीबी) उदय कुमार को वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाया गया है। ब्यूरो

तैयारी | सड़कों पर हादसे रोकने के लिए सोशल मीडिया पर शुरू की पहल

हादसों पर ब्रेक लगाएगा पुलिस का एबीसीडी मंत्र

शिमला। पहाड़ी और दुर्गम सड़कों पर सड़क हादसों को कम करने के लिए हिमाचल प्रदेश पुलिस ने ए-बी-सी-डी सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान शुरू किया है। सेवा, सुरक्षा और विश्वास के ध्येय वाक्य के तहत चलाए जा रहे इस अभियान का उद्देश्य स्थानीय लोगों के साथ प्रदेश में आने वाले पर्यटकों को भी सुरक्षित यातायात के प्रति जागरूक करना है।

पुलिस ने अपने सोशल मीडिया हेंड्ल पर सेफर रोड्स, सेफर पीपल, स्ट्रॉन्गर हिमाचल का संदेश देते हुए सड़क सुरक्षा के चार अहम नियमों को ए, बी, सी और डी से जोड़ा है।

अंधे मोड़ पर ओवरटेकिंग से बचने और हर सीट पर सीट बेल्ट लगाने का संदेश

अभियान के तहत ए का अर्थ अवाइड ओवरटेकिंग ऑन ब्लाइंड टर्न्स बताया गया है। पुलिस के अनुसार पहाड़ी सड़कों पर तीखे और अंधे मोड़ों पर जल्दबाजी में ओवरटेक करना हादसे का बड़ा कारण बन सकता है। ऐसे स्थानों पर चालक को सामने का रास्ता पूरी तरह साफ दिखाई देने तक इंतजार करने की सलाह दी गई है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि कुछ सेकंड की जल्दबाजी के बजाय सुरक्षित पहुंचना ज्यादा जरूरी है।

बी के तहतए बकल अपए एव्री सीट, एव्री राइड का संदेश दिया गया है। पुलिस ने वाहन में आगे और पीछे बैठने वाले सभी यात्रियों से सीट बेल्ट लगाने की अपील की है। विभाग के अनुसार सीट बेल्ट लगाने में कुछ ही सेकंड लगते हैं। सी के तहत कंट्रोल योर स्पीड, स्लो डाउन ऑन माउंटेन रोड्स का संदेश दिया गया है। पुलिस ने चालकों से पहाड़ी सड़कों पर वाहन की गति नियंत्रित रखने और परिस्थितियों के अनुसार धीमी गति से चलने की अपील की है। अभियान में 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे से कम की सुरक्षित गति बनाए रखने का संदेश दिया गया है।

डी का संदेश डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, ड्राइव सोबर, रीच होम सेफ है। प्रदेश पुलिस महानिदेशक अशोक तिवारी का कहना है कि हिमाचल पुलिस ने ड्राइव रिस्पॉन्सिबली संदेश के साथ आम लोगों और पर्यटकों से अभियान में सहयोग करने की अपील की है। ब्यूरो

महिला स्वास्थ्य जागरूकता पर निष्काम सृजन फाउंडेशन की कार्यशाला

by **Himachal Now** — September 7, 2026 in **Himachal** 0

0 SHARES 84 VIEWS

Share on Facebook Share on Twitter

शिमला : निष्काम सृजन फाउंडेशन द्वारा प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल पुरुषोत्तम तिवारी की सहमति एवं सौजन्य से अकाउंटेंट जनरल ऑफिस, गार्टन कासल, द मॉल, शिमला में कार्यरत आउटसोर्स महिलाओं के लिए महिला स्वास्थ्य

जागरूकता कार्यशाला आयोजित की गई।

डॉ. श्रेया वासुदेवा ने सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, यूटीआई तथा प्री एवं पोस्ट-मेनोपॉज़ से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं, उनके लक्षणों, बचाव एवं उपचार के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। लगभग 50 आउटसोर्स महिला र्मचारियों ने कार्यशाला में भाग लिया और स्वास्थ्य संबंधी अनेक प्रश्न पूछे। डॉ. वासुदेवा ने उनके प्रश्नों का सरल एवं ावहारिक तरीके से उत्तर दिया, जिससे सत्र अत्यंत उपयोगी एवं इंटरैक्टिव रहा।

स अवसर पर मननदीप सोंद ने महिलाओं के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न निःशुल्क स्वास्थ्य योजनाओं के रे में भी जानकारी दी, ताकि महिलाएं इन सुविधाओं का लाभ उठा सकें।
ाष्काम सृजन फाउंडेशन के सदस्यों ने प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल पुरुषोत्तम तिवारी का इस अवसर के लिए तहे ल से आभार प्रकट किया।

ाष्काम सृजन फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को विभिन्न गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति जागरूक करना, मय रहते लक्षणों की पहचान, जांच एवं उपचार के लिए प्रेरित करना है। इसी दिशा में फाउंडेशन द्वारा इससे पूर्व न्यू ामला में नगर निगम की सफाई मित्रों के लिए सर्वाइकल कैंसर की प्रारंभिक जांच हेतु पैप स्मीयर टेस्ट कैंप भी ायोजित किया जा चुका है।

ार्यशाला में फाउंडेशन की ओर से माला सिंह, तरुणा कौशल, अरुणा शर्मा, नीलम गुप्ता, उषा सूद, अनुराधा सूद, ादर्श सिंह सूद, गुरप्रीत सौंद एवं मननदीप। उपस्थित रहे।

Previous Post

निदेशक (परियोजनाएं) राजेश कुमार चंदेल ने किया नाथपा झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन का दौरा

Next Post

सेजिस ने मनाया 31वाँ स्थापना दिवस

Himachal Now